



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन, 1946 (श०)

संख्या - 618 राँची, शुक्रवार,

27 सितम्बर, 2024 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

तार्किक आदेश

24 सितम्बर, 2024

संख्या-07/हो०गा०(स्था०)-05/2013 (खण्ड)-5437--माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, द्वारा W.P. (S) No.-582/2017, दिनांक-25.08.2017 में पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

"Be that as it may, having gone through the rival submissions of the parties, this Court is of the considered view that the respondents have not considered the cases of the petitioners in right perspective. The order and directions of the Hon'ble Apex Court has not been considered in its true spirit. There was an specific directions of the Hon'ble Apex Court that while taking into consideration the fact, that the services of the Home Guards are used during an emergency and for other purposes and at the time of their duty, they are empowered with the power of police personnel and hence, they are entitled for minimum of the pay and the minimum of the pay was further clarified in the Contempt Petition that 'minimum of the pay' used in paragraph 22 of the judgment and order dated 11th March, 2015 means the basic pay+grade pay+ dearness allowance washing allowance.

In my view, the petitioners are entitled for the same benefits what has been held by the Hon'ble Apex Court. Accordingly, I hereby direct the respondents- State to reconsider the cases of the petitioners and other Home Guards of the State for giving them the benefits, in view of the order of the Hon'ble Apex Court passed in Cont. Petition (C) No. 699-700 of 2015 arising out of Civil Appeal No.2782-2783 of 2015. The matter is remanded back before the respondents-State to take a fresh decision in accordance with law."

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा गृह रक्षकों के मामले में उक्त वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा अन्य वाद में पारित न्यायादेश का उल्लेख करते हुए Basic Pay+Grade Pay+Dearness Allowance+Washing Allowance का लाभ के हकदार होने के बिन्दु पर प्रतिवादी राज्य को विधि अनुकूल निर्णय लेने का आदेश दिया है ।

2. उपरोक्त प्रासंगिक W.P. (S) No-582/2017 के आदेश के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में LPA No.-272/2018 दायर किया गया। उक्त LPA में पारित न्यायादेश दिनांक-12.01.2023 के कार्यकारी अंश कंडिका 6 एवं कंडिका-7 निम्नवत है:-

Para 6- "This Court, having heard the learned counsel for the parties and considering the facts of the given case as also the order passed by the learned Single Judge which is squarely based upon the order passed by the Hon'ble Apex Court in Civil Appeal No- 2782&2783 of 2015 wherein the Hon'ble Apex Court has been pleased to direct to make payment in favour of the Home Guards the minimum of pay scale which will include basic pay grade pay- dearness allowance washing allowance.

Para 7- The position of law is well settled that once the order has been passed by the Hon'ble Apex Court, under the provision of Article 141 of the Constitution of India, it becomes the rule of law and, as such, in that view of the matter, the State cannot oppose the order passed by the learned Single Judge since the order impugned is squarely based upon the order passed by the Hon'ble Apex Court in Civil Appeal No-2782 & 2783 of 2015, wherein at paragraph 22 following direction has been passed:-

*"22- In view of the discussion made above, no relief can be granted to the appellants either regularization of services or grant of regular appointments hence no interference is called for against the judgments passed by the Himachal Pradesh, Punjab and Delhi High Courts. However, taking into consideration **the fact that Home Guards are used during the emergency and for other purposes and at the time of their duty they are empowered with the power of police personnel, we are of the view that the State Government should pay them the duty allowance at such rates total of which 30 days (a month) comes to minimum of the pay to which the police personnel of State are***

entitled. *It is expected that the State Governments shall pass appropriate orders in terms of aforesaid observation on an early date preferably within three months."*

3. प्रसंगाधीन मामले में SLP (Civil) 25654/2023 The State of Jharkhand-Vs- Ajay Prasad and others दायर किया गया था, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त SLP को निरस्त कर दिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SLP में दिनांक-22.09.2023 को पारित आदेश निम्नवत् है:-

"Delay condoned.

In view of the order passed by this Court in Contempt Petition (C)No. 699-700/2015 in Civil Appeal No.- 2782-2783/2015 etc. dated 04.05.2016, we are not inclined to interfere in the order passed by the High Court. The special leave petition is dismissed. Pending applications stand disposed of."

उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेशों से स्पष्ट हैं कि भारत का संविधान के अनुच्छेद-141 के अन्तर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश बाध्यकारी प्रभाव रखता है। प्रासंगिक गृह रक्षकों के मामले में राज्य के पुलिस बल के समान 30 दिनों (प्रतिमाह) का न्यूनतम Basic Pay + Grade Pay + Dearness Allowance + Washing Allowance दिया जाना विधिसंगत है ।

4. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध सरकारी पत्र सं०-1-27021/2/2022-Ad (CD), दिनांक-24.01.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि होमगार्ड के कर्तव्य/जिम्मेदारी की तुलना पुलिस कर्मियों से नहीं की जा सकती है। समीक्षांपरांत SLP (Civil) Diary No.- 25654/2023 The State of Jharkhand & Ors. V/s Ajay Prasad मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-22.09.2023 को पारित उक्त आदेश के विरुद्ध Review Petition दायर किया गया, जिसका डायरी सं०-15239/2024 है। Review Petition (Civil) Diary No.- 15239/2024 The State of Jharkhand & Ors. V/s Ajay Prasad मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.07.2024 को पारित आदेश निम्नवत् है :-

"Delay condoned.

We have carefully persued the Review Petition as also the grounds in support thereof. In our opinion, no case for review of order dated 22.09.2023 is made out.

The Review Petition is, accordingly, dismissed. Pending application(s), if any, shall stand disposed of."

तदनुसार पारित न्यायादेश के आलोक में उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग के द्वारा सशर्त सहमति प्रदान की गयी कि विषयक मामले में गृह रक्षकों को पुलिसकर्मियों के समकक्ष दैनिक पारिश्रमिक दिये जाने से संबंधित आदेश संकल्प की निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा। उक्त के अनुपालन में विभागीय संकल्प संख्या-4596. दिनांक-10.08.2024 के द्वारा W.P. (S) No.-

582/2017 अजय प्रसाद एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-25.08.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में सभी प्रक्रियाओं का पालन कर गृह रक्षकों (स्वयंसेवकों) को पुलिसकर्मियों के समकक्ष दैनिक पारिश्रमिक दिये जाने के संबंध में संकल्प निर्गत किया गया है।

5. उल्लेखनीय है कि सदृश्य अवमाननावाद Cont. Case (Civil) No.-354/2021 (Grih Raksha Vahini Swam Sewak Sangh V/s The State of Jharkhand & Ors.) में दिनांक 16.08.2024 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया है-

"In view of the said order brought on record, it transpires that is a substantial compliance of the Court's order, as such, the contempt proceeding is dropped and the contempt petition is disposed of.

Personal appearance of the aforesaid officers are, hereby, dispensed with."

उक्त न्यायनिर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-4596, दिनांक-10.08.2024 निर्गतोपरांत उक्त अवमाननावाद को निष्पादित कर दिया गया है।

6. वर्तमान में Cont. Case (C) No.-98/2018 (Ajay Prasad V/s The State of Jharkhand & Ors.) With Cont. Case (Civil) No.-500/2020 (Rajesh Ram & Ors. V/s The State of Jharkhand & Anr.) में दिनांक-23.08.2024 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित न्यायादेश का अंश निम्नवत् है :-

"2. The petitioners working as Home Guard have been dragged up to the Hon'ble Apex Court and thereafter also review petition was filed. The State has lost before each and every forum. Instead of complying the order from the date this Court passed order in W.P.(S) 582 of 2017 i.e. 25.08.2017, they have complied the same seven years after the order passed by this Court i.e. from 10.08.2024. The stand of the State is not praiseworthy. The Hon'ble Apex Court on 04.05.2016, has granted one more opportunity to State to comply the order in true letter and spirit. The arrears has been calculated and paid to the persons w.e.f. 10.08.2024 who were actually are entitled for the said benefits from 25.08.2017.

3. Let the State take informed decision in view of discussion made above, within a period of four weeks.

Put up these cuses on 27.09.2024,"

उक्त के आलोक में दिनांक-25.08.2017 से बकाया पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया है। परामर्श के क्रम में वित्त विभाग द्वारा वित्तीय नियमावली के नियम-73 एवं 74 का उल्लेख किया गया है, जो निम्नवत् है :-

"73. जब तक आदेश या नियम में ही खास तौर से अन्यथा उपबन्धित न हो, सरकार के कार्यपालक आदेश मंजूरी सूचित करनेवाले अभिलेख, पत्र या तार के निर्गम की तारीख से प्रभावी होंगे और परिनियत नियम उस तारीख से जिस तारीख को ये पारित हुए थे। इसी तरह अधीन प्राधिकारियों की मंजूरी उस तारीख से प्रभावी जिस तारीख को आदेश सूचित किये जायें।

ऐसे सभी मामलों में सामान्य सिद्धान्त निम्न होना चाहिए-

किसी विशेष खर्च को मंजूरी त्योंही प्रवर्तित होगी, ज्योंही खर्च की पूर्ति के लिए निधि विनियोजित हो जाय, और यह तब तक प्रवर्तित न होगी जब तक कि निधि इसके लिए विनियोजित न हो जाय। विनिर्दिष्ट वर्षावधि के लिए आवश्यक खर्च की मंजूरी तब प्रवर्तित होती है जब प्रथम वर्ष के खर्च की न पूर्ति के लिए, निधि विनियोजित हो जाय और विनिर्दिष्ट अवधि में प्रति वर्ष प्रवर्तित रहेगी, यदि उस वर्ष निधि विनियोजित हो जाय।

74. वेतन-पुनरीक्षण या सरकारी सेवकों को रियायतें मंजूर करने में सक्षम सभी प्राधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक खास परिस्थिति न हो तब तक सरकार के विशेष अनुमोदन के बिना वित्तीय मंजूरी को भूतलक्षी प्रभाव न दिया जाय।"

विदित है कि गृह रक्षक सरकारी सेवक न होकर स्वयं सेवक है।

7. वर्णित उपरोक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली तथा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के न्याय निर्णय का सरकार स्तर से अक्षरशः पालन किया गया है। बकाया राशि भुगतान करने के संबंध में उपरोक्त पारित न्यायनिर्णयों में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। सदश्य अवमाननावाद (Cont. Case (Civil) No.-354/2021 Grih Raksha Vahini Swam Sewak Sangh V/s The State of Jharkhand & Ors.) में पारित न्यायनिर्णय के अनुपालन में विभागीय संकल्प संख्या-4596, दिनांक-10.08.2024 के निर्गतोपरांत वाद की कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया है। बकाया राशि का भुगतान किया जाना Judicious (विधिसम्मत) नहीं है।

अतएव वर्णित परिस्थिति में दिनांक-25.08.2017 के प्रभाव से गृह रक्षकों को पुलिसकर्मियों के समकक्ष दैनिक पारिश्रमिक दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

वंदना दादेल,

सरकार के प्रधान सचिव।
